www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 350

रोज़गार समाचार

सामाहिक

खण्ड 38 अंक 28 पृष्ठ 40 | नई दिल्ली 12 - 18 अक्तूबर 2013 | ₹ 8.00

रोज़गार सारांश

सं.लो.से.आ

● संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित.

अंतिम तिथि: 31.10.2013

रेलवे

● पूर्वी तट रेलवे, भुवनेश्वर को 1626 ट्रैकमैन, टोकन पोर्टर, सफाईवाला, अस्पताल अटेंडेंट और हेल्पर-II आदि की आवश्यकता

अंतिम तिथि: 11.11.2013

ओ.ई.एफ

● आप्टो इलेक्ट्रोनिक्स फैक्टरी, रायपुर को 191 फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर आदि की आवश्यकता

अंतिम तिथि: विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21वें दिन पड़ने वाली तारीख

भारतीय नौसेना

● भारतीय नौसेना द्वारा कार्यकारी शाखा के नौसैनिक बख्तरबंद निरीक्षण संवर्ग, शिक्षा शाखा और लॉजिस्टिक्स संवर्ग में स्थायी कमीशन (पीसी)/अल्पावधि कमीशन (एसएससी) के लिए अविवाहित पुरुष/महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित.

अंतिम तिथि: 25.10.2013

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष खण्ड में निम्नलिखित आलेख उपलब्ध है :

1. मतदाताओं का सशक्तिकरण/एम्पावरिंग वोटर्स

अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत के चालू खाता घाटे की नवीनतम प्रवृत्तियां

प्रशांत प्रकाश

किसी भी राष्ट्र के लिए भुगतान संतुलन एक सांख्यिकीय विवरण है, जिसमें एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान देश के निवासियों और अनिवासियों के बीच आर्थिक लेनदेन का सारांश शामिल होता है. 2010-11 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान संतुलन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति नियमावली 6 (बीटीएम-6) के अनुरूप रिपोर्टिंग पद्धति को अपनाया, जिसमें भुगतान संतुलन के लेनदेन को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है:- (i) चालू खाता (ii) वित्त खाता और (iii) वित्त लेखा लेनदेन.

चालू खाता: चालू खाते के अंतर्गत ''गुड्स'' यानी सामान (सामान्य वाणिज्यिक, गैर-सरकारी सोना आयात आदि सहित), ''सेवाएं'', ''प्राथमिक आय'' (कर्मचारियों के मुआवजे, निवेश, आय सहित) और ''गौण आय'' (व्यक्तिगत अंतरण और धन प्रेषण सहित) जैसे शीर्षों के तहत लेनदेन शामिल है. अब जबकि पूंजी खाता लेनदेन में भी सरकारी लेनदेन शामिल कर लिया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था के सोने के भंडारों (अर्थात् मौद्रिक प्राधिकारियों के स्वामित्व वाला सोना और जिसे आरक्षित परिसंपत्ति के रूप में रखा गया है), विशेष आहरण अधिकारों (स्पेशल ड्राइंग राइट्स), वित्तीय दावों और देयताओं आदि पर असर पड़ता है.

वित्त खाता: वित्तीय खाता लेनदेन के अंतर्गत अवांछित अंतरण जैसे प्रत्यक्ष निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी वाणिज्यिक ऋण आदि शामिल हैं.

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि चालू खाता लेनदेन को भी कभी-कभी ''दृश्य लेनदेन'' (वाणिज्यिक वस्तुओं, गैर-सरकारी सोना आयात आदि सहित) और ''अदृश्य लेनदेन'' (''सेवाएं'' और ''आय'' सहित) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें दृश्य लेनदेन आमतौर पर एक निर्दिष्ट अवधि में किसी अर्थव्यवस्था के **''व्यापार संतुलन''** को दर्शाता है.

वर्ष 2011-12 और 2012-13 में भारत का चालू खाता शेष क्रमशः सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत (78 अरब अमरीकी डॉलर) और 4.8 प्रतिशत (87 अरब अमरीकी डॉलर) घाटे के स्तर पर पहुंच गया. इसकी मुख्य वजह वाणिज्यिक वस्तुओं और सोना व्यापार घाटे से उत्पन्न विशिष्ट ''व्यापार घाटा'' धारणा को समझा जा रहा है. 2011-12 और 2012-13 में चालू खाता घाटे के जीडीपी के 4.6 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत के आंकड़ों की तुलना में भारत का व्यापार घाटा क्रमशः जीडीपी का 10.2 प्रतिशत और 10.8 प्रतिशत रहा. यह भी कि सामान्यतः ''अदृश्य'' अधिशेष में ''सेवा'' निर्यात और ''आय'' अंतरण, जैसे विदेश से धन प्रेषण, ने भारत में विस्तृत व्यापार घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. शेष चालू खाता घाटा वित्त पोषित करने के लिए वित्तीय खाते से संबंधित निवल पूंजी प्रवाहों (अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पूर्ववर्ती बीएमपी-5 के अनुसार पूंजी खाता) से धन मिल रहा है, हालांकि पोर्टफोलियो निवेश की मुख्य हिस्सेदारी होने के कारण इन प्रवाहों के अस्थिर स्वरूप के बारे में समय-समय पर चिंताएं प्रकट की जाती रही हैं. किंतु, हाल के समय में, जबकि ''अदृश्य'' घटक अवरुद्ध रहे हैं, वित्तीय संकट परवर्ती अवधि में पूंजी प्रवाह में महत्वपूर्ण कमी आई है.

भारत के चालू खाता घाटे की इन बुनियादी प्रवृत्तियों और उनके वित्त पोषण पैटर्न को देखते हुए वर्तमान चालू खाता घाटे के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान स्थिति में तेल, कोयला और लौह अयस्क का प्रमुख योगदान रहा है. भारत में 25,000 टन सोने का भंडार है और दुनिया में सोने की मांग में एक चौथाई हिस्सेदारी भारत की है. भारत में सोने का आयात 33 अरब अमरीकी डॉलर (2009-10 में) मूल्य से बढ़ कर 57 अरब अमरीकी डॉलर (2010-11 में) मूल्य पर पहुंच गया. 2012-13 में सोने का आयात 53 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का रहा है. देश के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जो 7.6 प्रतिशत (2005-06) से बढ़ कर 12.6 प्रतिशत (2011-12) पर पहुंच गई. वित्तीय संकट परवर्ती परिदृश्य में इसका प्रमुख कारण सोने के वैश्विक मूल्यों में बढ़ोतरी को माना जा रहा है क्योंकि विश्वभर में बचतकर्ता अपनी बचत को सुरक्षित माध्यमों में निवेश को तरजीह देते हैं. 2005 के बाद से सोने के दाम डॉलरों में दो गुना और रुपये में तीन गुना बढ़ चुके हैं. 2007 से 2012 की अवधि में अन्य क्षेत्रों के निवेश पर लाभ को पार करते हुए सोने पर निवेश लाभ में औसत वार्षिक बढ़ोतरी 23.7 प्रतिशत रही है. इसकी तुलना में निफ्टी (भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार) में वृद्धि 7.3 प्रतिशत और बचत जमा राशियों पर वृद्धि 8.2 प्रतिशत रही है (सहगल और अन्य 2012, वित्त वर्ष 2012-13 के आर्थिक सर्वेक्षण में उद्धृत). इसके अतिरिक्त, सोने में निवेश महंगाई से संरक्षण प्रदान करता है, जो वास्तविक लाभ को कम कर देती है (भारत में महंगाई 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः 9.6 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत रही). अतः भारत में हाल के दिनों में सोने की मांग और उसके आयात में हुई वृद्धि आभूषणों के लिए इसकी ऐतिहासिक खपत की बजाय निवेश गतिशीलता के कारण अधिक हुई है. बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा गोल्ड लोन यानी सोना ऋण योजनाएं इस मांग में और इजाफा करती हैं. 2008 में कुल स्वर्ण ऋण 20,000 करोड़ रुपये मूल्य के थे जबकि वर्ष 2012 में वे बढ़ कर 1,50,000 करोड़ रुपये मूल्य के हो गए. इसके

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारत का विकास - एक संक्षिप्त विश्लेषण

धर्म कीर्ति जोशी

पिछला दशक वास्तव में भारत के संबंधित जीडीपी वृद्धि की तरह अद्भुत रहा है. 2004-2008 के दौरान प्रति वर्ष तकरीबन 9 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए भारत ने अपने विश्वव्यापी अनुमान को हासिल किया है और उल्लेखनीय रूप से अपना कद ऊंचा किया है. 1930 की घोर मंदी के बाद भारत ने 2008-09 के दौरान 6.7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए और 2010-11 तक 9 प्रतिशत की वृद्धि को तेजी से पुनः हासिल करते हुए सबसे खराब विश्वव्यापी वित्तीय संकट (जीएफसी) में भी अपने लचीलेपन को प्रदर्शित किया है. किंतु, तेजी से निचले पायदान पर आना भी एक कठोर अनुस्मारक है कि शासकीय मामलों को संबोधित करने, हमारी बुनियादी संरचना निर्धारित करने, ढीली सुधार प्रक्रिया तथा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के मामले में यदि हम संतुष्ट होते हैं, तो हम विकास में नीचे खिसकने से बच नहीं सकते.

भारतीय अर्थव्यवस्था 2012-13 में एक दशक में 5 प्रतिशत की निचली दर से बढ़ी है और चालू वित्तीय वर्ष में उसके पूरा होने की आशा है. समय से पहले पूरे भारत में आया मानसून आशा की पहली किरण है. इस मानसून के दौरान सामान्य से 5 प्रतिशत अधिक संचित बारिश हुई. यह कृषि संबंधी वृद्धि को 4.5 प्रतिशत के प्रवाही दर से अधिक बढ़ाएगा. लेकिन कृषि भारत की सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 14 प्रतिशत ही है. 86 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद (उद्योग तथा सेवाएं) पिछले वर्ष की तुलना में धीमी गति से बढ़ने की आशा है. बाद में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2013-14 में पूर्ववत् सममूल्य होगी. जबकि अर्थव्यवस्था तकरीबन 9 प्रतिशत तक बढ़ी थी. लेकिन आज 5 प्रतिशत की वृद्धि को भी हासिल करना एक चुनौती है.

जबकि वृद्धि में शीघ्र सुधार की कोई आशा नहीं है, मध्यम अवधि की आशाओं को भी कम किया गया है. उदाहरणस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि ने भारतीय अर्थव्यवस्था वृद्धि के आउटलुक को मध्यकाल (2013 से 2017 तक) की तुलना में 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से 2013 में 5.7 प्रतिशत तक कम आंका गया है. योजना आयोग द्वारा 12वीं योजना अवधि (2012-13 से 2016-17 तक) हेतु 8 प्रतिशत जीडीपी की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पहुंच से बाहर है. चालू योजना अवधि के दौरान 6.5 प्रतिशत की वृद्धि को भी हासिल करने के लिए योजना के पिछले 3 वर्षों में 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि जीडीपी वृद्धि में अपेक्षित होगी, जो अति कठिन कार्य है.

भारत में मंदी का कारण आंशिक रूप से एक कमजोर वैश्विक पर्यावरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता. किंतु, वृद्धि में गिरावट का परिणाम घरेलू कारणों की वजह भी है. आज विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था संकुचित नहीं हो सकती, क्योंकि यह 2009 में हो चुका है (2009 में विश्व जीडीपी वृद्धि-0.5 प्रतिशत थी). बेशक, यह लगभग 2.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है किंतु भारत की जीडीपी वृद्धि 5 प्रतिशत की दर से कमजोर हो रही है. क्या इसका यह तात्पर्य है कि यह भारत में मंदी अकेला विश्वव्यापी कारण नहीं है.

इस संदर्भ में यह जीएफसी के बाद वृद्धि में तेज गति देने के पीछे के कारणों को पहचानने में निर्देशात्मक हो सकता है. 2009-10 और 2010-11 में विकास प्रवाह, काफी हद तक मौद्रिक और राजकोषीय दोनों प्रोत्साहन से प्रेरित था. ब्याज दरों में तेजी से कटौती और सरकारी खर्च में मांग पैदा करने के लिए विस्तार किया गया. जीएफसी अनुरूप वेतन आयोग के कार्यान्वयन को बल मिला. पुनरुज्जीवित वृद्धि को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिला, लेकिन यह भी व्यापक आर्थिक असंतुलन बनाया. ब्याज दर में कटौती और खपत उन्मुख खर्च उच्च मुद्रास्फीति का माहौल बनाया है. ऐसे में तब निजी-निवेश कंपनियों में सुधार नहीं हो सका. यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन चौथाई के रूप में विकास पर प्रभाव पड़ा.

प्रोत्साहन को अपरिहार्य रूप से वापस लिया जाना चाहिए- वर्तमान में, जिसके हम गवाह हैं, जो मुद्रास्फीति को निस्तेज करने के लिए ब्याज दरों को बढ़ा देता है और नियंत्रण के तहत राजकोषीय घाटे को सरकारी खर्च में खींच लेता है. ऐसे में निजी-निवेश दम तोड़ रहे हैं और लागू होने वाली परियोजनाएं सिकुड़ रही हैं. संक्षिप्त में, जब प्रोत्साहन को वापस लिया गया था, तब निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से आगे ले जाने की स्थिति में नहीं था. परिणाम स्वरूप, भारत की विकास दर तेजी से नीचे आ गई.

ब्याज दरों को कम करते हुए और सरकारी खर्चे को बढ़ाते हुए पुनरुज्जीवित वृद्धि की थोड़ी उम्मीद है और चूंकि निजी-निवेशों को पहले से मंद पड़ चुकी वृद्धि की संभावनाओं के आसपास होना चाहिए. नीति में निवेश बढ़ाने पर बल देना चाहिए तथा मुद्रास्फीति से लड़ने में खपत पर नहीं. आर्थिक वसूली और 2013-14 से अलग इसकी गति निजी क्षेत्र के निगमित निवेश के पुनर्जीवन पर आधारित होगी. 2013-14 में निवेश पुनर्जीवन में उत्तोलक तुलन-पत्रों के कारण बुनियादी संरचना के क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं, परियोजना उद्घोषणाओं और निधि चुनौतियों के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले संबोधन की नीति-संबंधी मामलों की आवश्यकता होगी.

भारत के विकास की संभावना बढ़ाने में आधारभूत सुधारों जैसे समान तथा सेवाकर, पारदर्शी और भविष्यदर्शी कराधान नीतियां, श्रम बाजार लचीलापन के प्रावधान तथा शासकीय मामलों के समाधान की भी आवश्यकता होगी. अंततः भारत की भौतिक बुनियादी संरचना में सुधार लाने और मुद्रास्फीति कम रखते हुए और कृषि संबंधी उत्पादकता में तेजी से विकास करने की क्षमता को बढ़ाएगा. खनन मुद्दों की छंटनी और लंबित परियोजनाओं का निपटारा करते हुए शीघ्रता से जीत हासिल की जा सकती है.

सरकार ने वित्तीय घाटे को सौम्य बनाने, एक मंत्रिमंडल समिति के गठन के माध्यम से निजी-निवेशों को गति देने, पेंशन बिल के निपटारा, भू-अर्जन को अधिक पारदर्शी बनाते हुए तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों हेतु खुदरा क्षेत्र को खोलने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की घोषणा की है. यहां दिए गए सभी कदम सकारात्मक हैं, किंतु वर्तमान अधोपतन में सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते.

(लेखक सीआरआईएसआईएल लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री हैं.
ई-मेल: dharmakirti.joshi@crisil.com)

पाक कला - एक कॅरिअर विकल्प के रूप में

क्या आप भोजन के प्रेमी हैं? क्या आप पाक कला का शौक रखते हैं? क्या आपकी पाक कला आपके मेहमानों को भाती है? क्या इन प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं? यदि हां, तो क्या आपने कभी पाक कला पर, कॅरिअर के एक विकल्प के रूप में विचार किया है? आज पाक कला देश में एक अत्यधिक लोकप्रिय कॅरिअर विकल्प है. शेफ (रसोइया) एक ऐसा पाक व्यवसायी है, जिसका मुख्य दायित्व भोजन पकाना और विदेशी व्यंजन तैयार करना होता है. एक शेफ के रूप में आपको एपेटाइज़र, स्नैक्स, सलाद, मुख्य व्यंजन एवं डिजर्ट्स जैसी विभिन्न खाद्य किस्में तैयार करनी होंगी. संभवतः आप अपनी रेसिपी बना सकते हैं और अपना भोजन (मैन्यू) तैयार कर सकते हैं. आप जैसे-जैसे अपने कॅरिअर में प्रगति करेंगे, आपको रसोई का अपना सामान रखना होगा. रसोई सप्लाई खरीदनी होगी. भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी रखनी होगी. अपव्यय से बचना होगा और व्यवसाय चलाना होगा. आपको स्टाफ रखना होगा और उसका प्रबंधन करना होगा तथा कार्य दक्षतापूर्वक करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करना होगा.

शैक्षिक योग्यताएं:

शेफ बनने के इच्छुक व्यक्तियों को होटल प्रबंधन में एक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा. यह पाठ्यक्रम भोजन बनाने तथा आतिथ्य उद्योग के प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक कार्यों में अपेक्षित कौशल दिलाता है. अंततः डिग्री एवं डिप्लोमा या पाठ्यक्रम खान-पान प्रौद्योगिकी तथा पाक कला में कौशल का विकास करते हैं. आज, इन पाठ्यक्रमों के प्रति लोगों का काफी झुकाव हो गया है. शेफ बनने के इच्छुक व्यक्ति इन पाठ्यक्रम को करते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य पाक-कौशल पर केंद्रित होता है. ये पाठ्यक्रम, इस क्षेत्र में कॅरिअर बनाने के लिए अपेक्षित व्यापक जानकारी भी देते हैं.

शेफ के रूप में अपना कॅरिअर प्रारंभ करने के लिए आपको उच्च स्तर के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है. स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम इस आवश्यकता को पूरा करते हैं और भोजन तैयार करने के सभी पहलुओं पर जानकारी देते हैं. यह पाठ्यक्रम कक्षा-सत्र, व्यावहारिक प्रशिक्षण, अतिथि संकायों द्वारा लेक्चर देने तथा उद्योग इंटर्नशिप का एक मिला-जुला कार्यक्रम होता है. पाठ्यक्रम के दौरान, आप विभिन्न प्रकार के भोजनों, मैन्यू, खाद्य भंडारण, रसोई के उपकरण, चाकू तकनीक, आहार, इन्वेंटरी तथा क्रय तथा सेवा शिष्टाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. चार वर्षीय पाठ्यक्रम करने के बावजूद हो सकता है कि कॅरिअर के पहले वर्ष आप आलू धोने एवं छीलने का कार्य करें.

कॅरिअर की संभावनाएं :

पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, आप रेस्तरां, डाइनिंग संस्थाओं, होटलों, बैंक्वेट्स, कॉफी शॉप्स, बेकरी, केटरर, एयरलाइंस, क्रूज़ लाइंस, अस्पतालों, सशस्त्र बलों तथा शैक्षिक संस्थाओं में रोज़गार तलाश सकते हैं. भर्ती करने वाले कुछ मुख्य होटलों में आई.टी.सी. होटल्स, ताज ग्रुप, ओबेराय, इम्पीरियल, मैरियॉट, लीला, पार्क, लेमन ट्री होटल्स एवं फोर सीजन्स शामिल हैं.

आपके कौशल तथा अनुभव के आधार पर आपका प्रारंभिक वेतन 15000 रु. से 30000 रु. के बीच हो सकता है. कनिष्ठ कार्यपालक शेफ जैसी भूमिका से आप अपने कॅरिअर में कार्यपालक शेफ, वरिष्ठ कार्यपालक साउस शेफ, साउस शेफ, डेमी शेफ डी पार्टी एवं कॉमिस जैसे पदों पर उन्नति प्राप्त कर सकते हैं. कार्यपालक शेफ के रूप में आपको रेस्तरां का पाक-कार्य करना होगा और मैन्यू बनाना होगा. साउस शेफ के पद पर आपको शेफ रखने तथा उनके कार्य निर्धारण का प्रबंधन करने जैसे प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक कार्य करने होंगे. लाइन शेफ के रूप में आप बेकिंग जैसे विशेषज्ञतापूर्ण पाक-कार्य करने होंगे.

कुछ कार्य अनुभव प्राप्त करने के बाद, आप एक फ्रीलांसर के रूप में या रेस्तरां मालिक के सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं. आप अपनी निजी खाद्य सेवा संस्थापना भी चला सकते हैं.

कौशल

शेफ का कार्य उतना आसान नहीं है जितना कि यह लगता है. यह उतना आसान नहीं है, जितना कि इसे टी.वी. कार्यक्रम में दर्शाया जाता है. एक परिष्कृत रसोई में अच्छा भोजन बनाने के कार्य में पर्याप्त दबाव सहन करना होता है और इसके लिए अच्छी शारीरिक एवं मानसिक सहन-शक्ति की आवश्यकता होती है. शेफ के रूप में आप से लंबे समय तक, विविध कार्य करने, कम समय में कार्य पूरा करने, अपव्यय रोकने तथा निरंतर श्रेष्ठ व्यंजन देने जैसे कार्य करने की प्रत्याशा की जाती है.

आपको अपनी स्मरण शक्ति में सुधार लाने तथा स्वाद एवं सुगंध की व्यापक समझ प्राप्त करने की आवश्यकता होती है. ताकि आप भोजन अच्छा तैयार कर सकें. इस क्षेत्र में सफलता के लिए सीखने, प्रयोग करने तथा नवप्रवर्तन की इच्छा होना अनिवार्य है. विभिन्न प्रकार की देशी एवं विदेशी पाक कला सीखने के अतिरिक्त, आपको अपनी प्रतिभा का भी पता लगाना होगा.

आप जैसे-जैसे उन्नति करते जाएंगे, दक्षता, अंतर-वैयक्तिक कौशल तथा नेतृत्व कौशल की आपकी आकांक्षा आपको प्रगति के पथ पर अग्रगामी रखेगी. अंत में ये सभी गुण आपको पाक उद्योग का अंश होने का अच्छा पारितोषिक देते हैं.

आजकल पाक कला एक सम्माननीय व्यवसाय है. यह व्यवसाय एक लुभावना, व्यावसायिक रूप से संतुष्टि देने वाला तथा आकर्षक कॅरिअर विकल्प है. आपके कॅरिअर के प्रारंभिक कुछ वर्ष संघर्षपूर्ण हो सकते हैं. किंतु जैसे-जैसे आप कार्य-अनुभव तथा कौशल प्राप्त करेंगे, आप इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो जाएंगे. यह व्यवसाय आपको कम समय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सहायता करता है. यह आपको बड़े होटलों, समारोहों तथा बड़ी हस्तियों से संबंध बनाने में भी सहायक है. इतना ही नहीं आप अपने निजी प्रदर्शन आयोजित कर सकते हैं तथा अपनी निजी पाक कला पुस्तकें प्रकाशित कर सकते हैं.

इसलिए, आप किसकी प्रतीक्षा में हैं? यदि आप सोचते हैं कि आप में एक अच्छा शेफ बनने के गुण हैं तो किसी अच्छे पाक कला संस्थान में प्रवेश लें और अपने कॅरिअर को उन्नत करें.

कॉलेज एवं पाठ्यक्रम

कॉलेज	पाठ्यक्रम	पात्रता	प्रवेश	वेबसाइट
रीजेंसी होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी कॉलेज, हैदराबाद	होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री	10+2	प्रवेश-परीक्षा में प्रदर्शन	www.rchmct.org
पॉयनियर होटल प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री	10+2	सामूहिक विचार-विमर्श एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन	www.pihmhyd.co.in
होटल प्रबंधन एवं खानपान संस्थान, हैदराबाद	आतिथ्य एवं होटल प्रशासन में बी.एससी. कार्यक्रम	10+2	प्रवेश-परीक्षा में प्रदर्शन	www.ihmhyd.org
भारतीय पाक कला अकादमी, हैदराबाद	खानपान प्रौद्योगिकी तथा पाक-कला में स्नातक डिग्री	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10+2	प्रवेश-परीक्षा में प्रदर्शन	www.iactchefacademy.com
होटल प्रबंधन संस्थान, औरंगाबाद	पाक कला में बी.ए. (आनर्स)	10+2	प्रवेश-परीक्षा तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन	www.ihma.ac.in
आई.टी.एम. पाक कला स्कूल, मुंबई	बकाल्यूरिएट इन क्यूलीनेरी आर्ट्स	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10+2	ट्रेड परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रदर्शन	www.itm.edu
वेलकम ग्रुप पाक कला अकादमी, मणिपाल	पाक कला में बी.ए.	न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ 10+2	अखिल भारतीय मणिपाल विश्वविद्यालय ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा सामूहिक विचार-विमर्श में प्रदर्शन	www.manipal.edu

(यह लेख TMIE2E अकादमी कॅरिअर केन्द्र, सिकंदराबाद (आं.प्र.)द्वारा दिया गया है. ई.मेल: faqs@tmie2e.com)

भारत के चालू...

पृष्ठ 1 का शेष

अतिरिक्त सोने के साथ और भी फायदे जुड़े हैं जैसे तरलता, काले धन को रखने का सुरक्षित स्रोत, बैंकिंग सुविधाओं के अभाव वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बचत का माध्यम होना आदि से भी सोने की मांग पर दबाव बढ़ता है.

हालांकि, वर्तमान चालू खाता घाटे के लिए सोने का आयात प्रमुख कारणों में से एक रहा है, लेकिन सोने से इतर व्यापार घाटे में भी तेजी से वृद्धि हुई है, जो 96 अरब अमरीकी डॉलर (2010-11) से बढ़ कर 131 अरब अमरीकी डॉलर (2011-12) और इससे भी बढ़ कर 144 अरब अमरीकी डॉलर (2012-13) मूल्य का हो गया. तेल और कोयले का बढ़ता खर्च और लौह अयस्क से निर्यात आमदनी में कमी आदि कुछ मुख्य कारण घाटे की प्रवृत्ति के मुख्य घटक हैं. तेल का खर्च भारतीय आयात व्यय में एक मुख्य घटक रहा है. तेल व्यय में बढ़ोतरी की वजह ऊर्जा की मांग में निरंतर वृद्धि और वैश्विक बाजारों में तेल के मूल्यों में बाहरी घटकों के कारण वृद्धि समझी जाती है. बाहरी घटकों में हाल में अरब देशों और मध्य-पूर्व के देशों में राजनीतिक-आर्थिक अस्थिरता शामिल है. अध्ययनों में अनुमान लगाया गया है कि कच्चे तेल के मूल्यों में प्रति बैरल 10 अमरीकी डॉलर की वृद्धि होने से भारत में चालू खाता असंतुलन करीब 8 अरब अमरीकी डॉलर बढ़ जाता है.

जहां तक कोयले की बात है, हालांकि भारत कोयला उत्पादन की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है, फिर भी भारत के कोयला आयात में निरंतर बढ़ोतरी हुई है. 2001 में 2 करोड़ टन कोयला आयात किया जाता था जो 2009 में बढ़ कर 7.4 करोड़ टन और 2012 में बढ़ कर 13 करोड़ टन पर पहुंच गया. देश में करीब 60 से 70 प्रतिशत बिजली कोयले से बनाई जाती है. इसलिए भविष्य में घरेलू उत्पादन दबावों के कारण कोयला आयात में बढ़ोतरी की आशंका है.

जहां तक लौह अयस्क का संबंध है, भारत ने 2009-10 में 11.7 करोड़ टन लौह अयस्क का निर्यात किया था, लेकिन इन आंकड़ों में 2012-13 में तेजी से गिरावट आई और लौह अयस्क का निर्यात घट कर 1.8 करोड़ टन रह गया. अनुमान है कि 2013-14 में भारत निर्यातक की बजाय लौह अयस्क का आयातक बन कर रह जाएगा. इस प्रकार लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक होने का भारत का दर्जा घट कर आयातक देश का हो जाएगा. इस प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार मुख्य कारणों में कर्नाटक में लौह अयस्क का उत्पादन सीमित किए जाने, गोवा में इसके उत्पादन पर प्रतिबंध लगने और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्थाओं और राज्य के हस्तक्षेपों के कारण ओड़िशा में पर्यावरण नियमों के कड़े प्रवर्तन जैसे कारण शामिल हैं.

इन विविध कारणों के चलते वर्तमान चालू खाता घाटा कम करने एक बहुतरफा कारगर नीति आवश्यक समझी जा रही है. निकट भविष्य में तेल आयात नियंत्रित करने की भी संभावना नजर नहीं आ रही है, ऐसे में चालू खाता घाटा नियंत्रित करने के लिए केवल तेल इतर घटकों का सहारा लेना होगा. जनवरी, 2012 से सरकार ने सोने पर आयात शुल्क धीरे-धीरे बढ़ा कर 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर पहुंचा दिया है. आभूषण उद्योग इसका विरोध यह कह कर कर रहा है कि इससे सोने की तस्करी बढ़ेगी. इस प्रकार जटिलताओं को देखते हुए तेल इतर चालू खाता घाटे को नियंत्रित करना समय की आवश्यकता है. सरकार इसके वित्त पोषण के लिए दीर्घावधि के स्थिर वित्त खाता प्रवाह के विकल्प तलाश कर रही है. हाल में सुझाए गए और आजमाए गए कुछ अन्य विकल्पों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को विदेश से धन जुटाने की अनुमति देना, भारत में सार्वभौम सम्पदा और पेंशन निधियों को आकर्षित करना, अनिवासी भारतीयों से धन उगाहना और विदेश स्थित भारतीय कंपनियों के ऋण लेने पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना आदि शामिल है.

आज विदेशी क्षेत्र का कारोबार सकल घरेलू उत्पाद के करीब 108 प्रतिशत है जबकि 1990-91 के दौरान यह सकल घरेलू उत्पाद का करीब 30 प्रतिशत था. ये आंकड़े भारत के निर्यात में विविधता लाने की आवश्यकता पर बल देते हैं. यह विविधता लक्षित देशों और आयात की जाने वाली वस्तुओं दोनों में ही लानी होगी. इतिहास से सबक लेना हमेशा विवेक सम्मत होता है, लेकिन प्रत्येक स्थिति या चुनौती अपने तरह की जटिलताएं लेकर आती है. भारत में चालू खाता घाटे की नवीनतम प्रवृत्तियां स्पष्ट करती हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सम्बद्धता बढ़ने से अवसर और चुनौतियां दोनों में ही इजाफा होता है. ऐसी स्थिति में सरकार की भूमिका सर्वाधिक निर्णायक हो जाती है, ताकि इन दो प्रवृत्तियों के बीच एक संतुलन कायम किया जा सके.

(लेखक सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटिबिलिटी-(सीबीजीए) के साथ कार्यरत हैं.
ई-मेल: prashant@cbgaindia.org)

डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.), भारत
सागर - 470003 (म.प्र.)
वेबसाइट: www.dhsgsu.ac.in, फोन: +91-7582-264055

विज्ञापन सं. 2013-14/एनटी/05

रोज़गार सूचना

निम्नलिखित गैर-शिक्षण पद को भरने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :

पद का नाम	वेतनमान	पद का ब्यौरा और श्रेणी
उप-रजिस्ट्रार	पीबी-3; 15600-39100+जीपी 7600	04 (01-अपिव, 01-अजा, 01-अना और 01-अना, धारणाधिकार रिक्ति के मुकाबले

शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आवेदन पत्र, आयु आदि के संबंध में विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट **www.dhsgsu.ac.in** से डाउनलोड किए जा सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15/10/2013 को 5.30 (अपराह्न) है. आवेदन पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा सहायक रजिस्ट्रार (भर्ती) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर-470003 (म.प्र.) को भेजा जाए.

रो.स. 28/33 **रजिस्ट्रार**

रोज़गार समाचार

ईरा जोशी अपर महानिदेशक
निधि पांडे निदेशक, महाप्रबंधक एवं मुख्य संपादक
डॉ. ममता रानी संपादक
नलिनी रानी संपादक (विज्ञापन एवं संपादकीय)
इरशाद अली (संपादक)
आफ़ाक़ अहमद एहसानी संपादक
सूर्यकांत शर्मा व्यापार व्यवस्थापक
विनोद कुमार मीणा संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
पी.के. मंडल वरिष्ठ कलाकार
केपी मणिलाल लेखा अधिकारी

संपादकीय कार्यालय
रोज़गार समाचार
पूर्वी खण्ड IV तल-5, रामकृष्णपुरम
नई दिल्ली-110066

ई-मेल-संपादकीय : enewsedit@gmail.com
विज्ञापन : enewsadvt@yahoo.com

संपादकीय :	: 26163055
विज्ञापन	: 26104284
टेलीफैक्स	: 26193012
वितरण	: 26107405
टैलीफैक्स	: 26175516
प्रोडक्शन	: 26177529
लेखा (विज्ञापन)	: 26193179
लेखा (वितरण)	: 26182079

दिल्ली पोस्टल पंजीकरण संख्या डीएल.एसडब्ल्यू 1/4100/2012.14 यू. (सी.).107/2012.14 पूर्व शुल्क के बिना डाक में डालने की अनुमति आर.एन.आई. 28729/76 एन.डी.पी.एस.ओ. नई दिल्ली 12/14.10.2013 (₹ 8) प्रकाशन तिथि : 10.10.2013

प्रधानमंत्री का संयुक्त राज्य अमरीका दौरा- एक सिंहावलोकन

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 25 सितम्बर से 1 अक्तूबर 2013 तक संयुक्त राज्य का दौरा किया. अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ द्विपक्षीय बैठक की, न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा के 68वें सत्र में सामान्य बहस को संबोधित किया और बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान सहित पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की. प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में व्यापारिक अग्रणियों (बिजनेस लीडर्स) को भी संबोधित किया.

डॉ. मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति ओबामा ने यह पुष्ट किया कि दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच साझेदारी अपने सड़सठ साल के इतिहास में किसी भी समय की तुलना में मजबूत है. संयुक्त वक्तव्य ने दोनों पक्षों ने व्यापार और सैन्य अभ्यास सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की सहारना की. नेताओं ने रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान, सह-विकास एवं सह-उत्पादन में अपनी भागीदारी को बढ़ाने के साधन के रूप में रक्षा सहयोग पर एक संयुक्त घोषणा का समर्थन करते हुए रक्षा व्यापार सहयोग को और मजबूत करने की अपनी इच्छा को पुनः पुष्ट किया.

यह अवलेख करते हुए कि दोनों ओर से व्यापार 2001 से पांच गुणा बढ़कर लगभग 100 मिलियन डालर हो गया है, राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने सहमति व्यक्त की कि द्विपक्षीय व्यापार को और अतिरिक्त पांच गुणा बढ़ाने में कोई भी अपराजेय बाधा नहीं है. ओबामा ने विश्वास प्रकट किया कि भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए चालू भारतीय आर्थिक सुधार और नीतिगत उपाय आर्थिक विकास को तेज करेगा, व्यापार के लिए बेहतर रास्ते खुलेंगे और दोनों देशों में रोजगार के अवसरों का सृजन करेगा. इस संबंध में नेताओं ने खासकर भारत-अमरीकी व्यापार और निवेश संबंधों के सुदृढ़ीकरण में भारत और अमरीका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग और आईटी समर्थित सेवा उद्योग की भूमिका और योगदान को मान्यता दी.

सिविल नाभिकीय विद्युत क्षेत्र में राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने स्पष्ट किया कि प्रकिया पर दोनों सरकार की सहमति से अमरीकी परमाणु कंपनियों और न्यूक्लीयर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एन पी सी आई एल) के बीच वाणिज्यिक वार्ता आगे बढ़ी है. उन्होंने इस घोषणा का स्वागत किया कि एन पी सी आई एल और अमरीकी न्यूक्लीयर कंपनी वेस्टिंगहाउस ने भारत में गुजरात में एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र के विकास के लिए प्रारंभिक करार को अंतिम रूप दिया है. इस आधार पर नेताओं ने एन पी सी आई एल और अमरीकी कंपनी वेस्टिंगहाउस और जेनेरल इलेक्ट्रिक- हितैची से गुजरात और आंध्र प्रदेश में नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए आवश्यक काम को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया. दोनों पक्षों ने भारत-अमरीकी सिविल नाभिकीय सहयोग करार के पूर्ण और समय पर कार्यान्वयन के लिए अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराया.

2009 में दोनों नेताओं द्वारा शुरू किए गए अमरीकी-इंडिया पार्टनरशिप टु एडवांस क्लीन एनर्जी (पी ए सी ई) से लाखों भारतीय परिवारों के लिए ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करने की आशा की जाती है. अधिक लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा संसाधन की पहुंच की उपलब्धता के विस्तार हेतु राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने हाल में ऊर्जा पहुंच की कमी वाले के लिए अभिनव नवीकृत ऊर्जा समाधान के तीव्र नियोजन के लिए पी ए सी ई की पहल प्रोमोटिंग एनर्जी एसेस थ्रू क्लीन एनर्जी (पी ई ए सी ई) शुरू करने के प्रस्ताव का समर्थन किया.

जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों नेता अन्य बातों के साथ-साथ बहुपक्षीय दृष्टिकोण, जिसमें आर्थिक रूप से व्यवहार्य और तकनीकी रूप से संभाव्य विकल्पों पर आधारित एच एफ सी के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से कम करने के मॉन्ट्रियल घोषणा की विशेषज्ञता और युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यू एन एफ सी सी सी) और उत्सर्जन की गणना और रिपोर्टिंग के लिए शामिल क्योटो प्रोटोकॉल पर विचार करने के लिए हाइड्रो फ्लूरोकार्बन (एच एफसी) पर भारत-अमरीकी कार्य बल के तुरंत आयोजन पर सहमत हुए.

दोनों नेताओं ने दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की भी पुनरीक्षा की.

यू एन सामान्य सभा के 68वें सत्र की सामान्य बहस में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अपने नीति निर्णय ढांचे में विकासशील देशों के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने दोनों देशों के बीच और प्रगाढ़ रक्षा सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया.

वृद्धि और समावेशी विकास पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्वभावतः सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण, बहुपक्षीय विकास बैंकों सहित वद्धित निवेश प्रवाह, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और खुली बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था की आवश्यकता है. गरीबी महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक चुनौती रही है और इसके उन्मूलन पर विशेष ध्यान देने और नए समेकित प्रयास की आवश्यकता है. यह प्रमुखता 2015-पश्चात् विकास एजेंडा को बांधेगा, जिसका निराकरण सदस्य राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि इसे व्यापक संभव समर्थन और स्वीकृति मिले.

देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार के प्रयासों के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने सभा से कहा कि इस मामले का विभिन्न तरह से समाधान किया जा रहा है. विधायन ने शिक्षा तक पहुंच को विस्तारित किया है और ग्रामीण आजीविका को सुनिश्चित किया है. उन्होंने सूचित किया कि भारत खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम तैयार कर रहा है और लोक सेवाओं की सुपुदर्गी और लोगों के लाभ के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी से इसे सज्जित किया जा रहा है.

आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हर जगह सुरक्षा और स्थायित्व के लिए गंभीर खतरा रहा है और इसका खामियाजा विश्व भर में निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है. राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद खासकर भारत के लिए चिंता का विषय है. यह इस कारण से भी है कि हमारे क्षेत्र में आंतकवाद का अधिकेंद्र हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में स्थित है.

भारत-शिमला करार के आधार पर द्विपक्षीय वार्ता के जरिए जम्मू तथा कश्मीर सहित सभी मुद्दों के समाधान के लिए निष्ठापूर्वक वचनबद्ध है. तथापि इस दिशा में प्रगति के लिए यह अनिवार्य है कि पाकिस्तान और इसके अधीन आने वाले क्षेत्र का उपयोग भारत के विरुद्ध आंतकवाद को उकसाने के लिए न किया जाए. इस तथ्य की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि जम्मू तथा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत की अखंडता से कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता है.

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विरुद्ध बढ़ती मिश्रित चुनौतियों, चाहे वह साइबर सुरक्षा हो, गैर प्रसार हो या आंतकवाद, के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय आम राय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी द्वारा नाभिकीय आयुध मुक्त और अहिंसक विश्व व्यवस्था के लिए व्यापक कार्य योजना लाने के 25 वर्ष बाद इस साल हमें नाभिकीय प्रसार के विरुद्ध प्रयास को सुदृढ़ करना चाहिए और हमें समयबद्ध, चिरंतन, गैर-भेदभावकारी, चरणबद्व और प्रामाणिक नाभिकीय निशस्त्रीकरण का अनुसरण करना चाहिए.

न्यूज़ डाइजेस्ट

- *उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बैलट पेपर/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में एक आवश्यक प्रावधान शामिल करने का निर्देश दिया है कि जिसमें मतदाताओं को 'उपर्युक्त में से किसी को भी वोट नहीं' का एक अन्य विकल्प देने को कहा गया है. यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं देना चाहते तो यह उन्हें सशक्त बनाएगा कि वे गोपनीयता के अधिकार के साथ वोट नहीं देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करें.* ***(अधिक जानकारी के लिए www.rojgarsamachar.gov.in देखें वेब विशेष)***
- *केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन कर अलग तेलंगाना राज्य के गठन को स्वीकृति दे दी है. हैदराबाद दस साल के लिए दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी होगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रिसमूह के गठन को भी मंजूरी दे दी है जो राज्य के सभी क्षेत्रों के निवासियों के मौलिक अधिकारों की गारंटी के साथ उनकी सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वैधानिक और प्रशासनिक उपायों पर गौर करेगा.*
- *राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(आरयूएसए) को सरकार की स्वीकृति मिल गई है. 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्वायत्त कॉलेजों/कॉलेजों के समूह को राज्य विश्वविद्यालयों में बदलकर 80 नए विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई . पेशेवर/तकनीकी कॉलेजों सहित 100 नए कॉलेजों को स्थापित किया जाएगा और मौजूदा 54 कॉलेजों को मॉडल डिग्री कॉलेजों में तब्दील किया जाएगा. 150 विश्वविद्यालयों और 3,500 कॉलेजों को ढांचागत विकास विशेषकर पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि के लिए अनुदान दिया जाएगा. आरयूएसए के तहत 5,000 फैकल्टी की भर्ती में भी सहयोग दिया जाएगा.*
- *केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित स्वीकृति दी:*

  राष्ट्रीय सार्वभौमिक इलैक्ट्रॉनिक सुलभता नीति, विकलांगता के आधार पर भेद-भाव को समाप्त करने के साथ-साथ इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को समान रूप से सभी के लिए सुलभ कराने पर ज़ोर देती है. यह नीति स्थानीय भाषा के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों (शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग-दोनों) तक समान रूप से और बिना किसी बाधा के इलैक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी उत्पादों तथा सेवाओं की पहुंच को आसान बनाएगी.
- *500 बिस्तर वाला जनरल अस्पताल, 300 बिस्तर वाला सुपर स्पैशैलिटी अस्पताल, एक नर्सिंग कॉलेज और पैरामैडिकल स्कूल सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपी एफआईएलएमएस) के निर्माण का प्रस्ताव.*
- *मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों से सम्बद्ध समिति ने संयुक्त अरब अमीरात की एतिहाद एयरवेज़ को जेट एयरवेज़ की 24 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मेसर्स एतिहाद एयरवेज़ को जेट के प्रत्येक 10 रुपए के 27.2 मिलियन शेयर खरीदने की अनुमति दे दी जो 2057.66 करोड़ रुपए तक की राशि (उससे अधिक नहीं) के लिए चुकता इक्विटी पूंजी जारी करने के बाद 24 प्रतिशत तक राशि होगी. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी. मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद 2057.66 करोड़ रूपए का विदेशी निवेश देश में आएगा.*
- *केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से संबंधित अध्यादेश और विधेयक (संसद में लंबित) को वापस ले लिया है. उच्चतम न्यायालय ने 10 जुलाई को कहा था कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए किसी भी सांसद या विधायक को तत्काल अयोग्य करार दिया जाएगा.*
- *भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2013-14 की पहली तिमाही के लिए भुगतान संतुलन (बीओपी) का आंकड़ा जारी किया. चालू खाता घाटा 21.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 प्रतिशत) है जिसमें मुख्य रूप से धनराशि पूंज़ी प्रवाह से आई है. अगस्त, 2013 तक सकल कर संग्रहण में वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है.*
- *भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि क्रेडिट कार्ड संबंधी धोखाधड़ी होने पर बैंकों को हर्जाना भरना होगा. क्रेडिट कार्ड स्वाइप मशीनों पर सिक्युरिटी बढ़ाने की समय-सीमा बढ़ाने से इंकार करते हुए आरबीआई ने बैंकों को आदेश दिया है कि निर्देशों का पालन नहीं होने की स्थिति में कोई धोखाधड़ी होती है तो ऐसे में कार्ड धारकों को एक हफ्ते में मुआवज़ा देना होगा. इसके अतिरक्त आरबीआई ने बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों को दी जा रही 'ज़ीरो परसेंट इंटरेस्ट' संबंधी योजनाओं पर रोक लगा दी है.*
- *राष्ट्रपति ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर शुद्धता और सच्चाई की पहचान, 'खादी के निशान' का शुभारंभ किया. खादी का कोई संस्थान या कोई व्यक्ति जो खादी से संबंधित काम करता हो खादी चिह्न के लेबल, स्टीकर या टैग के बिना न तो कपड़ा बेच सकता है न ही उसका व्यापार कर सकता है. कोई भी खादी उत्पाद किसी भी रूप में बिना खादी चिह्न के नहीं बेचा जा सकता. इस क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के मद्देनज़र इस चिन्ह से खादी के उत्पादों को पहचान मिलेगी तथा इनकी बिक्री भी बढ़ेगी.*
- *राष्ट्रपति ने 1 अक्तूबर, 2013 को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार . वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया. वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने तथा जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का राष्ट्रीय पुरस्कार महाराष्ट्र के वृद्ध सेवाश्रम को प्रदान किया गया. माता-पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों की देख-रेख और कल्याण (एमडब्ल्यूपीएससी) अधिनियम, 2007 पर अमल करने तथा वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मध्यप्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय विभाग को प्रदान किया गया.*
- *पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यटन मानचित्र पर भारत के हिमालय को केंद्र बिंदु में लाने के लिए 'अतुलनीय भारतीय हिमालय के 777 दिन' के अभियान की शुरूआत की है. 777 दिनों के इस अभियान की अवधि के दौरान भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान द्वारा पर्वतारोहण अभियानों के शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क पर्यटन मंत्रालय देगा.*
- *मलेशिया के कुआलालम्पुर में 8वीं महिला एशिया कप 2013 में भारत ने चीन को 3.2 से हराकर कांस्य पदक जीता. नेशनल स्टेडियम में तीसरे/चौथे स्थान के लिए खेले गए इस मैच का फैसला पैनल्टी शूटआउट से हुआ.*
- *भारत की सानिया मिर्जा और जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक की जोड़ी ने टोक्यो में पैन पैसिफिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है. इस जोड़ी की यह एक साथ पहली खिताबी जीत है. इसके बाद इस जोड़ी ने चीन की राजधानी में आरंभिक दौर में भी जीत दर्ज की.*

उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण

- ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक
- भारत में अध्यन हेतु 10 लाख रुपये तक
- विदेश में अध्यन हेतु 20 लाख रुपये तक
- वेबसाइट **www.nhfdc.nic.in** पर ऑनलाइन आवेदन करें

नि:शक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलेपमेंट कार्पोरेशन

(नि:शक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

रेड क्रॉस भवन, सैक्टर-12, फरीदाबाद-121007

दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371

ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in रो.स. 28/95

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के लिए ईरा जोशी, अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटिंग प्रेस अमर उजाला पब्लिकेशन लिमिटेड, सी.21 व 22, सेक्टर.59, नोएडा.201301 में मुद्रित, रोज़गार समाचार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ईस्ट ब्लाक.IV, लेवल.5, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली.110066 द्वारा प्रकाशित, संपादकः डॉ. ममता रानी